(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उद्योगों की सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 30 अक्तूबर, 1998 को "1998-99 की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा" सम्बन्धी एक विवरण जारी किया।

(ख) से (घ) ऊपर उल्लिखित नीति में वे उपाय शामिल होते हैं जो मूलत: दीर्घावधिक स्वरूप के होते हैं। इन उपायों का उद्देश्य सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय प्रणालियों के अनुरूप पूंजीगत प्रर्याप्तता के निर्धारण और अन्य विवेकपूर्ण मानदण्डों को सुदृढ़ बनाकर मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाना हैं। ये उपाय भविष्यगामी स्वरूप के हैं और एक निश्चित समयावधि में चरणबद्व रूप से कार्यान्वित किए जाएंगे।

बैंकिंग प्रणाली में नकदी-निधि की स्थिति सन्तोषजनक हैं और औद्योगिक क्षेत्र के ऋण सम्बन्धी आवश्यताएं पर्याप्त रूप से वहन की जा सकती हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक अर्थात् 6 नवम्बर, 1998 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए संसाधनों के कुल प्रवाह में 19,701 करोड़ रूपए की वृद्वि प्रदर्शित हुई हैं जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 15,338 करोड़ रूपए की वृद्वि की तुलना में अधिक हैं। पूर्वोवत को ध्यान मे रखते हुए अल्पावधि उपायों अर्थात् बैक दर, नकदी प्रारक्षित अनुपात, सांविधिक नकदी अनुपात और रिपो दर में किसी परिवर्तन की घोषण नहीं की गई हैं।

मूल्य वृद्वि को रोकने के लिए उपाय

1747. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मूल्य वृद्वि की समस्या को हल करने के लिए कुछ नये कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उपायों के कारण मूल्य वृद्वि में कितने प्रतिशत गिरावट आयी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार मूल्य वृद्वि को रोकने के लिए समुचित कदम कब तक उठाने का विचार रखती हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) मूल्य वृद्वि को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई हैं और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ओ.जी.एल. के तहत इसके शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई हैं।
- नेफैड को आर्थिक सहायता प्रदत्त बिक्री के लिए प्याज की अधिप्राप्ति करने के लिए कहा गया।
- भारतीय खाद्य निगम के भण्डारों से गेहूं की खुले बाजार में बिक्री को अधिकृत किया गया हैं।
- ओ.जी.एल. के तहत दालों के आयात की अनुमति दी गई हैं और दालों के आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क को समाप्त कर दिया गया हैं।
- सार्वजानिक वितरण प्रणाली हेतु राज्यों/संघ शसित प्रदेशों के लिए 1.5 लाख टन खाद्य तेल की डिलीवरी सुनिश्चित की गई हैं।
- वनस्पति विनिर्माताओं द्वारा तेल का आयात करने पर 4 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
- मूल्य स्थिति पर निगाह रखने के लिए मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में सचिवो की समिति (सी.ओ.एस.) की नियमित रूप से बैठक होती हैं।

मंत्रिमण्डल सचिव ने आश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्वि को रोकने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक की। तदन्तर, 27.11.98 को हुई मंत्रियों के सम्मेलन की बैठक में अनेक कार्रवाई संबंधी मुद्दे तय किए गए, जिन पर संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही हैं।

(ख) और (ग) अधिकतर सब्जियों की कीमतों में दिसम्बर, में अद्योगामी प्रवृत्ति दिखाई देनी शुरू हो गई हैं और प्याज तथा आलूओं की कीमतों में पर्याप्त कमी आई हैं। इस कमी के आगे भी जारी रहने की सम्भावना हैं।

Transfer of IT Officials

1748. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of Income Tax Officials have been transferred within three months affecting the ongoing investigation against a number of politicians; and